नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 290
दि. 21.02.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण करेंगे

प्रधानमंत्री भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन करेंगे और संपूर्ण दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री भारत की सबसे तेज मेट्रो - मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे

पहली बार अपनी तरह की पहल के तहत, नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो एक ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होंगी

ये परियोजनाएं भारत में एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करती हैं

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ का दौरा करेंगे। दोपहर में करीब 12:30 बजे, प्रधानमंत्री शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वे मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे, प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है।

180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ, नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है। नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएगें।

कॉरिडोर का शुरूआती स्टेशन सराय काले खान, इस उद्घाटन के साथ शुरू होने वाले चार नमो भारत स्टेशनों में से एक है। यह रणनीतिक रूप से एक प्रमुख मल्टी-मॉडल हब के रूप में स्थित है, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड को सरलता से जोड़ता है। शुरू होने वाले अन्य तीन नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम मेरठ में हैं।

प्रधानमंत्री मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, जो नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होगी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे

तेज मेट्रो प्रणाली होगी, जिसकी अधिकतम परिचालन गति लगभग 120 किमी प्रति घंटा होगी। मेट्रो सभी निर्धारित पड़ावों सहित पूरी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय करेगी। एक ही बुनियादी ढांचे पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का यह निर्बाध एकीकरण, तेज रफ्तार वाली अंतर-शहरी यात्रा और शहर के भीतर सुगम आवागमन के लिए मददगार साबित होगा, जो भारत में एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इससे सड़क यातायात में भीड़ कम होगी और नतीजतन वाहनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में खासी कमी आएगी।

ये परियोजनाएं शहरी गतिशीलता को बदलने और नागरिकों के जीवन को सरल बनाने वाली निर्बाध, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को और गति प्रदान करेगी।

सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति, महामहिम सेबेस्टियन पिल्लई ने उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन से भेंट की

(जीएनएस)।सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति, महामहिम सेबेस्टियन पिल्लई ने आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में माननीय उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन से भेंट की। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा में सहयोग बढ़ाने, ट्रांसशिपमेंट के अवसरों को तलाशने और दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच में सुधार के महत्व पर जोर दिया। नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, पूरे सेशेल्स में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के विस्तार पर भी चर्चा की।

दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य और

आवास क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें जन-केंद्रित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो सीधे नागरिकों को लाभान्वित करती हैं।

यह उल्लेख करते हुए कि भारत और सेशेल्स इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रों के बीच लंबे समय से चले आ रहे प्रवासी संबंधों और सुदृढ़ सांस्कृतिक एवं आपसी जन-संपर्क की सराहना की और आने वाले वर्षों में इस साझेदारी को इसकी पूर्ण क्षमता तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

शिक्षामित्रों को 10 की जगह 18 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे

सीएम योगी की बड़ी घोषणा: शिक्षामित्रों को 10 की जगह 18 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे, अनुदेशकों को 17 हजार

लखनऊ , (जीएनएस)।

सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब शिक्षा मित्रों को अप्रैल से 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों को 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने तत्काल भुगतान व्यवस्था लागू करने की बात भी कही है।

प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों और अनदेशकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षामित्रों को अब 10 हजार की जगह 18 हजार और अनुदेशकों को नौ हजार की जगह 17 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। यह मानदेय अप्रैल माह से भुगतान किया जाएगा। इससे करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और करीब 25 हजार अनुदेशक लाभांवित होंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को तीसरी बड़ी घोषणा की। इससे पहले वह विधान परिषद में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं तो विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन की भी बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। शुक्रवार को वह करीब दो घंटे 50 मिनट के वक्तव्य में सर्वाधिक समय शिक्षा व्यवस्था पर दिया।

सुधार की चर्चा करते हुए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। यह भी बताया कि सभी शिक्षकों को पांच लाख तक के कैशलेस चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। बजट पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर तंज भी कसा। कहा कि सपा सरकार इन्हीं शिक्षामित्रों को सिर्फ तीन हजार मानदेय देती थी। उन्होंने उच्च शिक्षा का जिक्र करते हुए ग्रेडिंग सुधार, ब्रिटेन जाने के लिए स्कालरशिप योजना, स्टार्टअप सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया।

बनेंगे दो इकोनॉमिक जोन

लिकटेंस्टीन रियासत के वंशानुगत राजकुमार एचएसएच प्रिंस एलोइस का भारत दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर, लिकटेंस्टीन रियासत के वंशानुगत राजकुमार प्रिंस एलोइस ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी, 2026 को समिट के दौरान प्रिंस एलोइस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और लिकटेंस्टीन के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि की। अक्टूबर 2025 में भारत-टीईपीए मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने का स्वागत करते हुए, दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई गति प्रदान करेगा।

एमएसपी पर खरीद को और सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध करने के निर्देश

दलहन आत्मनिर्भरता को गति देने एवं टरढ पर सुनिश्चित खरीद के लिए नाफेड की व्यापक समीक्षा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास 12, सफदरजंग पर नेशनल एग्रीकलचरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमि. (नाफेड) की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित करने तथा संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) के अंतर्गत संचालित खरीद कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टरढ पर खरीद को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया कि खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विशेष रूप से तुअर, उड़द तथा मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के उत्पादन एवं खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इन फसलों के लिए प्रस्तावित 6 वर्षीय 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत

उत्पादन वृद्धि, उन्नत बीजों की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग एवं प्रभावी विपणन तंत्र विकसित करने पर चर्चा हुई। इस मिशन का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्यों के साथ समन्वय मजबूत किया जाए तथा खरीद एवं भंडारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे बाजार में मूल्य स्थिरता बनी रहे और किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी, अपर सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, नाफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ गोलमेज सम्मेलन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह सेवा तीर्थ में एआई और डीपटेक स्टार्टअप के सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक की।

इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स प्रमुख सेक्टरों में जनसंख्या-स्तरीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में, वे उन्नत निदान, जीन थेरेपी और कुशल रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करते हैं जिससे कि अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचाई जा सके। कृषि में, वे उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता के लिए भू-

स्थानिक और अंडरवॉटर इंटेलीजेंस का लाभ उठाते हैं। इस समूह में साइबर सुरक्षा, नैतिक एआई, अंतरिक्ष, न्याय और शिक्षा तक स्थानीय भाषा में पहुंच के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यम उत्पादकता को सुदृढ़ करने के लिए पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित उद्यम भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एआई-संचालित नवोन्मेषण में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण करता है।

एआई स्टार्टअप्स ने भारत द्वारा अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की।

मम्मी-पापा की मंजूरी के बिना नहीं कर सकेंगे लव मैरिज, राज्य सरकार लेकर आई नया बिल

(जीएनएस)।

गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन और लव मैरिज के नियमों में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का मसौदा विधानसभा में पेश किया गया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब प्रेम विवाह (लव मैरिज) के लिए आवेदन करने पर दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता को इसकी जानकारी दी जाएगी। माता-पिता को वॉट्सएप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए शादी की सूचना दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 40वें दिन विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

विधानसभा में नियम-44 के तहत नई प्रक्रिया की घोषणा उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने की। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन का उद्देश्य 'लव जिहाद' और भगाकर शादी जैसे मामलों पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 30 दिनों तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अगर उचित सुझाव मिलते हैं तो उनमें संशोधन किया जाएगा। इसके बाद नियम लागू कर दिए जाएंगे।

- विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन दोनों पक्षों और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। आवेदन को विधिवत नोटराइज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही पहचान प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सरकारी आईडी) लगाना होगा।

- आवेदन संबंधित समुदाय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप (सैंपल-1(क)) में जमा होगा। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, विवाह निमंत्रण पत्र, दूल्हा-दुल्हन और गवाहों की पासपोर्ट साइज फोटो तथा विवाह की रस्म दशार्ने वाली फोटो शामिल होंगी।

दूल्हा-दुल्हन को एक डिक्लेरेशन भी देना होगा कि क्या माता-पिता को विवाह की जानकारी दी गई है। अब दूल्हा-दुल्हन को अपने माता-पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार विवरण भी देना अनिवार्य होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के बाद 10 कार्यदिवस के भीतर माता-पिता को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से सूचित करेगा। इसके बाद आवेदन जिला या तालुका रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। सभी शर्तें पूरी होने पर 30 दिनों के बाद विवाह पंजीकृत किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात प्रमाणपत्र जारी होगा।

यूएस कोर्ट ने उतारा ट्रंप का टैरिफ भूत, लताड़ से निकल गई दादागीरी

(जीएनएस)।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए नेशनल इमरजेंसी से जुड़े एक कानून का सहारा लिया था। अदालत के इस फैसले ने उनके उस बड़े और विवादास्पद दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यापक इस्तेमाल किया था। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा।

6-3 के बहुमत से आया फैसला

जजों ने 6-3 के बहुमत से निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने 1977 के कानून का उपयोग अपनी संवैधानिक शक्ति से आगे बढ़कर किया। यह फैसला उन व्यवसायों और 12 अमेरिकी राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आया, जो ट्रंप के एकतरफा फैसले से प्रभावित हुए थे। इन राज्यों में अधिकांश डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्य शामिल थे।

किन राज्यों और कंपनियों ने चुनौती दी

टैरिफ के खिलाफ दायर मुकदमों में तीन अलग-अलग मामले शामिल थे। यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर

द फेडरल सर्किट ने पांच छोटे आयातक व्यवसायों और 12 राज्यों- एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वरमोंट- के पक्ष में फैसला दिया। इसके अलावा, वाशिंगटन स्थित एक फेडेरल जज ने लर्निंग रिसोर्सेज नाम की एक खिलौना बनाने वाली कंपनी के पक्ष में भी फैसला सुनाया।

भारत पर बेवजह टैरिफ

हालांकि अमेरिका दशकों से व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, ट्रंप ने इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का आधार बनाया और IEEPA का आ'न किया। फरवरी और मार्च 2025 में उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए, यह कहते हुए कि फेंटेनाइल और अवैध दवाओं की तस्करी नेशनल इमरजेंसी है। जबकि भारत के खिलाफ ऐसे कोई तर्क नहीं मिले तो जबरन टैरिफ थोपा गया।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और भारतीय बाजार पर क्या असर?

भारतीय बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द किए जाने का असर भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी पड़ेगा। अब जब रेसीप्रोकल टैरिफ हट गए हैं, तो भारत को अमेरिका को होने वाले अपने कुल निर्यात के 55 प्रतिशत हिस्से पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा और इन सामानों पर सिर्फ स्टैंडर्ड एमएफएन टैरिफ ही लागू होंगे। हालांकि भारत के बाकी कुछ निर्यात पर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ जारी रहेंगे, यानी स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25 प्रतिशत टैक्स लगता रहेगा। वहीं राहत की बात यह है कि स्मार्टफोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दवाइयों जैसे कुल 40 प्रतिशत निर्यात पर कोई अमेरिकी टैरिफ नहीं लगेगा। ऐसे में इस नए बदलाव को देखते हुए भारत को अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर दोबारा सोचने की जरूरत हो सकती है।

भारतीय एक्सपोर्टर्स का मिलेगा रिफंड?

एक्सपर्ट्स मानें तो, सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने के बाद उन एक्सपोर्ट्स को पैसा वापस मिल सकता है, जिन्होंने अमेरिकी बाजारों में अपने सामान को बेचने के लिए टैरिफ के रूप में काफी पैसा अमेरिकी सरकार के खजाने में भरा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे किस तरह से लागू किया जाता है, इस पर भारत सहित दुनियाभर की नजरें लगी हैं। क्योंकि इसमें शर्तों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दिसंबर 2025 से आंकड़े छुपाने लगे थे ट्रंप

ट्रंप प्रशासन का दावा था कि इन टैरिफ से अगले 10 सालों में अमेरिका को खरबों डॉलर का राजस्व मिलेगा। हालांकि, प्रशासन ने 14 दिसंबर के बाद से टैरिफ वसूली के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक

सलोंन, रायबरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में आज नगर पंचायत सलोंन के गोरही वार्ड स्थित रिया पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व सभासद इसरार हैदर रानू ने बोलते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वंचितों महिलाओं दिव्यांगों बाल अपराध लोगों को कानूनी सहायता निशुल्क उपलब्ध कराता है। आप सभी लोग आज आप निवास व सरकारी योजनाओं के लिए जिला परिषद सेवा प्राधिकरण के सदस्यों से

संपर्क करके अपना काम कर सकते हैं। वहीं इसरार हैदर ने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए उनके दायरे में रहकर के करना चाहिए। भारत का कानून यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। भारत का संविधान ही भारत का गौरव है । गोष्ठी में पीएलबी नागार्जुन प्रसाद गुप्त ने 22 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाले ग्राहक मेगा जागरूकता शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि यह शिविर दिव्यांग महिलाओं बच्चों सरकारी योजनाओं सुमंगला कन्या योजना सामूहिक विवाह योजना पेंशन आवास राशन कार्ड आज की सीधे पत्रों को लाभ दिलाया जाएगा। वहीं पीएलबी माधुरी ने 14 मार्च को होने वाले लोक अदालत के भी जानकारी के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य अलीम सर, सईद अहमद, मरियम, संगीता ,जैनब बानो, आलिया बानो, जमीला , आरफा , एवं विद्यालय के तमाम छात्र-छात्रा उपस्थिति रही।

सुप्रीम कोर्ट ने लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और व्यवस्था की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग लापता होते हैं और यह सिलसिला जारी है। इनमें से अधिकतर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां होती हैं। इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में अकेले दिल्ली से 800 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर ने एक बार फिर इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। फिर भी, हैरानी की बात यह है कि इस आपराधिक समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय प्रयास नहीं किया गया है। लापता व्यक्तियों का राज्यवार विश्लेषण भी बहुत कम उपलब्ध है। अब तक कितने लोग मिले हैं? और इन मामलों के पीछे कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कुछ ही दिनों में अकेले दिल्ली से 800 लोग लापता हो गए, तो पूरे देश से कितने लोग लापता हुए होंगे?

शून्य त्रुटि एजेंसी

इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों में लापता बच्चों की घटनाओं के पीछे किसी विशेष समूह की संलिप्तता की जांच करने को कहा है। इसके लिए, न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की संख्या और सभी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है, तो क्या केंद्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वह ऐसे कदम उठाए?

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर से लापता बच्चों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जहां सभी राज्य ऐसी घटनाओं का विवरण जमा कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की उदासीनता स्पष्ट है। केंद्र सरकार ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और संबंधित कार्यवाही से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। लेकिन केंद्र सरकार अदालत में ऐसा जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट से इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 2023 में देशभर में 8 लाख से अधिक लोग लापता हुए। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। गुजरात में भी यह समस्या गंभीर है, जहां शहरों से लेकर गांवों तक लोगों के लापता होने की खबरें लगातार आती रहती हैं। खासकर छोटे बच्चों या लड़कियों की संख्या अधिक है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है

सेवा, समर्पण और विश्वास की पहचान बना संजीवनी हॉस्पिटल, अब जल्द मिलेगा ब्लड बैंक की सुविधा

कौशांबी। जनपद में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याय बन चुका संजीवनी हॉस्पिटल आज हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। निस्वार्थ सेवा और समर्पण के उद्देश्य से स्थापित इस अस्पताल ने अपनी स्थापना के साथ ही क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीत लिया।

संजीवनी हॉस्पिटल की नींव 20 अप्रैल 2013 को करन चौराहा स्थित एक किराए के भवन में डॉ. मनीषा चौधरी (टइइर, स्त्री एवं प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ एवं लेप्रोस्कोपिक गाइनी सर्जन) द्वारा रखी गई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था—क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं को बेहतर, सस्ता और भरोसेमंद इलाज उपलब्ध कराना।

अस्पताल खुलने की सूचना मिलते ही सराय अकिल, कनैली, मंझनपुर, पश्चिम सरीरा सहित प्रयागराज और अन्य जनपदों से भी मरीज इलाज के लिए आने लगे।

डॉ. मनीषा चौधरी की कुशलता, सरल स्वभाव और मरीजों के प्रति सेवा भावना ने अस्पताल को लगातार आगे बढ़ाया। मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिलने से अस्पताल की पहचान तेजी से मजबूत हुई। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए दिनाँक 23

फरवरी 2023 में नए और आधुनिक भवन में अस्पताल का विस्तार किया गया, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़े अस्पताल का संचालन शुरू हुआ।

संजीवनी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की परामर्श सेवा, नार्मल एवं सीजेरियन डिलीवरी, लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन विधि) सर्जरी, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, प्लास्टिक सर्जरी, हड्डी, स्पाइन और न्यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन, नेत्र रोग, कान-नाक-गला विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ईसीजी, 24 घंटे फामेर्सी, प्राइवेट एवं एसी युक्त डीलक्स रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के कारण अब क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता।

करीब 13 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहा संजीवनी हॉस्पिटल अब एक नई पहल के तहत संजीवनी ब्लड बैंक एवं कंपोनेंट सेंटर की शुरूआत करने जा रहा है। यह सुविधा शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

संजीवनी हॉस्पिटल आज न केवल एक अस्पताल, बल्कि सेवा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। कम खर्च में बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाओं के साथ यह अस्पताल क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहा है।

जिला संवाददाता मोहम्मद नसीम कौशांबी

मुफलिसी के अंधेरे में इंसानियत की रोशनी: अमरावती की शादी में 31 हजार की मदद से लौटी रौनक

कौशाम्बी-- (जीएनएस)।

24 फरवरी को अमरावती की बारात आनी है। शुक्रवार को तिलक जाना था। जिस घर में ढोलक की थाप और बधाई गीत गूंजने चाहिए थे, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। टेनशाह आलमाबाद गांव की गुड्डी के आंगन में खुशी की जगह चिंता ने डेरा डाल रखा था। घर में अन्न का दाना तक नहीं था और बेटी की शादी सिर पर खड़ी थी।

पति राकेश गौतम की मौत के बाद दो बेटों और दो बेटियों की जिम्मेदारी गुड्डी के कंधों पर आ गई। बड़ा बेटा पैर टूटने के कारण काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करने वाली गुड्डी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर बेटी अमरावती की शादी गढ़वा गौहानी में तय की। लेकिन जैसे-जैसे तिलक और बारात की

तारीख नजदीक आई, आर्थिक तंगी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया।

जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो गुरुवार को वह मदद की आस लेकर मंझनपुर कोतवाली पहुंच गई। अपनी व्यथा सुनाते हुए उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी एक मां की बेबसी देख भावुक हो उठे। पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से लिया और उसे नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अध्यक्ष के पास भेजा।

मामला सामने आते ही अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी ने शुक्रवार को स्वयं गांव पहुंचकर परिवार की स्थिति का जायजा लिया। सूना आंगन, टूटी चारपाई और उदास चेहरों को देखकर माहौल गमगीन हो गया। उन्होंने तत्काल 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही तिलक समारोह में कन्या पक्ष की ओर से दी जाने वाली आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था कर स्वयं बेटी के घर पहुंचकर सहयोग सौंपा।

अध्यक्ष की इस पहल से गांव में चर्चा का माहौल है। मदद मिलते ही गुड्डी के चेहरे पर राहत साफ झलकने लगी। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत, सात यात्री घायल

(जीएनएस) ।कौशांबी

जनपद के थाना कोखराज क्षेत्र में शुक्रवार भोर लगभग 3 बजे नेशनल हाईवे पर थाना के ठीक सामने तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद भरवारी के चमंधा निवासी मुन्ना पुत्र दान सिंह, महमदपुर निवासी राजू भारती पुत्र जगरूप, दीपू पुत्र बिहारी, सूरज पुत्र मानसिंह, मुकेश पुत्र बनवारी लाल, गोविंद पुत्र लवकुश तथा एक अन्य व्यक्ति गुरुवार रात दावत से लौट रहे थे। भोर में जब वे कोखराज थाना के सामने पहुंचे तो भरवारी रोड की ओर मुड़ने के दौरान प्रयागराज की तरफ से आ रहे ट्रक से स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग अंदर फंस गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही कोखराज थाना पुलिस भी तत्काल पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दीपू की हालत अधिक गंभीर है।

दुर्घटना के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सड़क पार करते समय पर्याप्त सावधानी न बरतने से हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ग्राम पंचायत कुल्ली में विकास कार्यों की शिकायत पर पहुंची जांच टीम

तहसील दिवस पर की गई शिकायत के 21 बिंदुओं की हुई जांच, अभिलेखों की पड़ताल

खखरेरू/फतेहपुर विजयीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कुल्ली में कराए गए विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर जनपद स्तरीय तीन सदस्यीय जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

ग्राम निवासी शिकायतकर्ता नरसिंह पुत्र धनराज नारायण सहित अन्य ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बबली देवी पर आरोप लगाया था कि ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया

है। इस संबंध में तहसील दिवस पर लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें 21 बिंदुओं पर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

शिकायत के आधार पर जनपद से गठित तीन सदस्यीय टीम ग्राम पंचायत कुल्ली पहुंची और संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू की।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम सभा की कार्ययोजना से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिनकी टीम ने सचिव कुल्ली की उपस्थिति में जांच की।

जांच अधिकारी शरद विक्रम (सहकारिता विभाग) ने बताया कि शिकायत में विकास कार्यों के फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया था। प्राथमिक जांच में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि कार्य योजना को लेकर शिकायत की गई थी, उनमें से कार्य नहीं किया गया न हीं भुगतान किया गया अभिलेखों की भी जांच की जा रही है।

रीबोर (नलकूप पुनर्भरण) के संबंध में उन्होंने कहा कि पुराना रीबोर मौके पर नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद की जाएगी। जांच से संबंधित तथ्यों की सत्यापित प्रति शीघ्र ही शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी।

'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में शामिल हुए कुकिंग आइकॉन

भारत के कुकिंग आइकॉन संजीव कपूर अब तक के सबसे जबरदस्त कुक-ऑफ के लिए कलर्स के 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में शामिल हुए

कलर्स के लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के किचन में अब तक अफरा-तफरी, कॉमेडी और कुकिंग का पागलपन देखा गया है, लेकिन इस हफ़्ते एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कंटेस्टेंट इस उम्मीद से आए कि शेफ हरपाल सिंह सोखी की जानी-पहचानी एनर्जी और उनके ट्रेडमार्क 'लेकिनङ्घ' से दिन का चैलेंज अनाउंस होगा। इसके बजाय, वहाँ भारत के कुकिंग लेजेंड संजीव कपूर खड़े थे। रिएक्शन ने सब कुछ बता दिया। पहले शॉक। फिर यकीन न होना। और फिर एक पूरा फैन मोमेंट।

जब हर कोई भारतीय कुकिंग के सबसे बड़े नाम को अपने किचन में देखकर बहुत खुश था, तो एक बड़ा सवाल भी घूम रहा था, 'हरपाल जी कहाँ हैं?' क्योंकि आमतौर पर, जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो शेफ हरपाल आगे आते हैं, मुश्किल को कम करते हैं और कभी-कभी प्रेशर कम करने के लिए जजिंग कैटेगरी भी कम कर देते हैं। इस बार, वह आराम कम नहीं हो रहा था। शेफ संजीव कपूर ने इसे कड़ा और आसान रखा। इंस्ट्रक्शन्स को ठीक से फॉलो करें। कोई शॉर्टकट नहीं। कोई मोल-भाव नहीं।

पहला चैलेंज था बॉम्बे हलवा - एक ऐसी डिश जो देखने में तो आसान लगती है लेकिन उसमें छिपा है टेक्निक का बारूद ही बारूद। पाँच परफेक्ट पीस। तरबूज का फ्लेवर। सॉफ्ट, बाउंसी टेक्सचर। ग्लॉसी फिनिश। बैलेंस्ड मिठास। एक गलती और स्टार गायब हो सकता था। प्रेशर असली था, और घबराहट भी। फिर भी, शो का जोश कम नहीं हुआ। सुदेश लहरी उसी शेफ के सामने खाना बनाने का अपना एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाए, जिसे देखते हुए कई लोग बड़े हुए हैं। कृष्णा अभिषेक ने प्रेशर में भी 'मर ढूंढ लिया, जबकि अर्जुन बिजलानी ने टीजिंग जारी रखी। हंसी जारी रही, बस हाथ थोड़े कांप रहे थे।

फिर आया कुक टू, भाप बड़ी सालन। हैदराबादी सालन और राजस्थानी बड़ी का एक बोल्ड मिक्स, जो दो अलग-अलग कुकिंग वर्ल्ड को एक प्लेट पर ले आया। यह अफरा-तफरी से कम और कंट्रोल, बैलेंस और टेक्निक के बारे में ज्यादा हो गया। इस सब के दौरान, शेफ संजीव कपूर सिर्फ मौजूद नहीं थे, बल्कि वह माहौल बना रहे थे। एक मजेदार लेकिन यादगार रहने वाला कि खाना बनाना मजेदार है, लेकिन यह एक क्राफ्ट भी है।

इस जोश के बीच, संजीव कपूर ने अपने अनुभव के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकाला। उन्होंने कहा, 'लाफ्टर शेफ्स में आने का अनुभव मेरी सोच से भी बेहतर रहा - सब कुछ सच में बहुत बढ़िया था। चाहे यहां बैठी ऑडियंस हो या भारती, जिस गंभीरता और जुनून के साथ आप सभी खाना बनाते हैं, वह बहुत तारीफ के काबिल है। जब भी खाने की दुनिया में कुछ बड़ा होता है, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मुझे सच में नहीं लगता कि भारत में इससे बड़ा कुकिंग पर आधारित कोई शो है।'

देखें निविया सॉफ्ट और रियलमी स्मार्टफोन्स मिलकर प्रेजेंट कर रहे हैं 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' जिसे को-पावर किया है एन्वी परफ्यूम्स, कैच मसाले, किसान चटनीज, विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर और राजधानी बेसन ने, स्पेशल पार्टनर्स कोका कोला और हिम्स आयुर्वेद हॉस्पिटल्स के साथ, हर शनिवार-रविवार रात 9:00 बजे सिर्फ कलर्स पर!

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने नए एम्स के अध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों के नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया

रोगी-केंद्रित मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोगी देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

नए एम्स को संस्थागत मूल्यों को बनाए रखते हुए रोगी देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में विश्व मानक स्थापित करने चाहिए: श्री नड्डा

एम्स को संरचित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को गहरा करना चाहिए: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी एम्स में कार्यात्मक जन औषधि और अमृत फामेर्सी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का आ'ान किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के बीच संस्थागत विनिमय तंत्र पर जोर दिया

क्षमता विस्तार से एम्स में देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित नए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थानों (एम्स) के अध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों के नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, अंतर-संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए एम्स संस्थानों का एक सुदृढ़ एवं एकजुट नेटवर्क स्थापित करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि एम्स नेटवर्क के विस्तार के वर्तमान चरण में यह नेतृत्व सम्मेलन प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रोगी

देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है जिसमें रोगी-केंद्रित मॉडल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने संरचित रोगी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और रोगी संतुष्टि बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया एम्स प्रणाली से जुड़े संस्थागत मूल्यों को संरक्षित करते हुए रोगी देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में विश्व-स्तरीय मानक स्थापित करेगा।

नए एम्स के विकास के विभिन्न चरणों को देखते हुए मंत्री महोदय ने पारस्परिक सहयोग और सुनियोजित समन्वय के महत्व पर बल दिया ताकि संस्थान समन्वित तरीके से एक साथ विकसित हो सकें। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 20 एम्स ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी अनुसंधान संघ की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस पहल को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संस्थागत नेतृत्व को प्रशासनिक दक्षता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का मिश्रण करना होगा।

शासन की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए मंत्री महोदय ने दोहराया कि प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जबकि कार्यकारी निदेशक दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभावी संस्थागत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यात्मक भेद का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने पारंपरिक प्रथाओं से आगे बढ़कर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देने का आ'ान किया।

मंत्री महोदय ने अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने, विशेष रूप से निदान और नैदानिक निर्णय लेने में एआई के एकीकरण का आग्रह किया और एम्स के नियमित कामकाज के एक नियमित घटक के रूप में टेलीमेडिसिन सेवाओं को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और संस्थानों की सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों को मजबूत करने का भी आ'ान किया।

मानव संसाधन विकास के विषय पर मंत्री महोदय ने ज्ञान मानकों और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना संकाय भर्ती में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रतिवर्ष कम से कम चार साक्षात्कार आयोजित करने का सुझाव दिया और एम्स में संकाय भर्ती में हाल ही में हुई वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने दोहराया कि नर्सिंग और गैर-संकाय कर्मचारियों के लिए एनओआरसीईटी और सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) जैसी संरचित प्रक्रियाओं को नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें समय पर नियुक्तियों पर विशेष जोर दिया जाए।

मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि सभी एम्स में जन औषधि केंद्र और अमृत फामेर्सी जैसी सुविधाएं स्थापित और संचालित की जाएं ताकि सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने एम्स और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के बीच शिक्षकों और छात्रों के आदान-प्रदान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विकसित करने का आ'ान किया, जिसमें शिक्षण और नर्सिंग क्षमता निर्माण में एम्स की अग्रणी भूमिका हो।

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों, आनुवंशिक विकारों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में। एम्स की संख्या में विस्तार को स्वीकार करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ी हुई क्षमता से स्थापित मानकों में कमी नहीं आनी चाहिए।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे

ओवैसी यदि जनाधार मजबूत रखें तो मुस्लिम राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा। समाजवादी पार्टी को रणनीति बदलनी पड़ेगी, ताकि वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस को तो मुस्लिम समर्थन वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सपा-कांग्रेस को ओवैसी के चलते मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चिता उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी एकजुटता और रणनीतिक वोटिग ने कई चुनावों के परिणाम बदल दिए हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब बीस प्रतिशत है, जो सवा चार सौ विधानसभा क्षेत्रों में से सवा सौ से अधिक पर अपना प्रभाव डालती है। इनमें सत्तर क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत तीस से अधिक रहता है। कभी कांग्रेस का मजबूत आधार रहे ये मतदाता अब हवा के रुख के अनुसार अपना पाला बदल लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा उन दलों को सत्ता से दूर रखना रहता है, जो हिदू हितों की बात प्रमुखता से करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख करने में जरा भी गुरेज नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अधिकांश मुस्लिम वोट मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी वुछ हिस्सा हाथ लगा। बीते निकाय चुनावों में यह पैटर्न बदला, जब मुस्लिम मतदाताओं ने एक दल के पीछे न जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना। पमिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छोटे दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अधिक समर्थन मिला। इस बदलाव ने राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम नेताओं ने अपनी अलग परटियां बनाकर इन मतों को लुभाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसे पुराने संगठनों के बाद पीस पार्टी तथा उलेमा काउंसिल ने मैदान संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ गठबंधन कर कई प्रत्याशी उतारे, लेकिन सफलता सीमित रही। इन प्रयासों से मुस्लिम वोटों में वुछ बिखराव तो हुआ, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अब सबसे अधिक चिता का विषय है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उभार। बिहार चुनावों में पांच सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका ली हैं। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सौ सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी और अब 2027 के चुनावों के लिए ओवैसी की पार्टी ने 200 क्षेत्रों को चार भागों में बांटकर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसकी वजह भी है। पमिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बरेली में पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। निकाय चुनावों में यहां उसके प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। ओवैसी का यह उभार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी की नींद उड़ा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक में भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर चिता जताई गई। बिहार और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के उदाहरण देते हुए सपा नेताओं द्वारा यहां तक कहा गया कि ओवैसी के बिना गठबंधन से नुकसान हो सकता है। वुछ सांसदों ने गठबंधन का सुझाव दिया, हालांकि शिवपाल यादव ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। फिर भी मिशन 2027 की रणनीति पर विचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चिता भी सामने आ चुकी है। संसद भवन परिसर में सांसद इमरान मसूद से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में घुसने से रोकने की बात कही। सभी इसे ओवैसी पर तंज मान रहे हैं। खरगे ने चेतावनी दी कि ऐसा होने पर सभी को नुकसान होगा। यह वीडियो राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ चुका है। बहरहाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़े होंगे, यह सवाल सभी को वुरेद रहा है। यदि पैटर्न पुराना रहा तो अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। लेकिन ओवैसी के बढ़ते प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 70 से अधिक क्षेत्रों में वोट बंट सकते हैं।

आयुष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के स्वदेशी आयुष मॉडलों का लाभ उठाया जाएः सचिव, आयुष मंत्रालय

इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट में आयुषः दर्शकों की व्यापक भागीदारी ने नागरिक केंद्रित डिजिटल आयुष समाधानों में बढ़ती दिलचस्पी को रेखांकित किया

(जीएनएस)।

इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट 2026 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के पैवेलियन में दर्शकों, नवोन्मेषकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का तांता लगा रहा। इन सब ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए मंत्रालय के कृत्रिम मेधा (एआई) समर्थित समाधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पैवेलियन में एआई चालित चैटबॉट्स और योगा पॉस्चर एआई ने खास तौर से काफी दिलचस्पी पैदा की। कंप्यूटर दृष्टि आधारित समाधान योगा पॉस्चर एआई उपयोगकताओं को योग आसनों के आकलन, सुधार तथा अधिक सटीक और सुरक्षित ढंग से अभ्यास में समर्थ बनाता है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के महानिदेशक वैद्य रविनारायण आचार्य और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं का अवलोकन किया जो डिजिटल पहलकदमियों और प्रौद्योगिकी समर्थित जन स्वास्थ्य टूल्स की झांकी पेश करते हैं। श्री कोटेचा ने आयुष क्षेत्र में सेवा डिलीवरी, अनुसंधान, शिक्षण और प्रशासन को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए प्रौद्योगिकी संचालित हस्तक्षेपों के सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आयुष ग्रिड टीम की सराहना की। आयुष सचिव ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्वम एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटा और गूगल समेत अन्य प्रमुख संस्थाओं की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और सारगर्भित संवाद किए।

श्री कोटेचा ने नागरिकों, चिकित्सकों और संस्थानों की सहायता के लिए विकसित एआई आधारित चैटबॉट्स की व्यावहारिक उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पारंपरिक स्वास्थ्यसेवा की संरचना में डिजिटल बुद्धिमत्ता को शामिल करने के मौजूदा प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्यसेवा के कायाकल्प के लिए स्वदेशी एआई क्षमताओं के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डाटा की प्रामाणिकता, समावेशिता और वैश्विक अंतरसंचालनीयता को सुनिश्चित करते हुए आयुष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के स्वदेशी एआई मॉडलों का लाभ उठाया जाना चाहिए। आयुष सचिव ने कहा कि मापनीय और जनकेंद्रित स्वास्थ्यसेवा समाधानों की रचना के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ कृत्रिम मेधा को जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ा जाना चाहिए।

शिखर सम्मेलन में आयुष पवेलियन 'आयुष ग्रिड' की व्यापक संरचना को प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक 'माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (एमएआईएसपी) है। यह एक एकीकृत डिजिटल गेटवे है जो स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान, औषधीय पौधों की जानकारी, औषधि प्रशासन और सार्वजनिक पहुंच को एक ही मंच के माध्यम से जोड़ता है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और संस्थानों के लिए प्रामाणिक आयुष सेवाओं तक निर्बाध और तकनीक-समर्थित पहुंच सुनिश्चित करना है।

एआई-सक्षम उपकरणों का सजीव प्रदर्शन दर्शकों के लिए संवाद का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इंटेलिजेंट चैटबॉट्स व्यक्तिगत कल्याण मार्गदर्शन और सेवाओं तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि 'योग पोस्चर एआई' प्रणाली यह प्रदर्शित करती है कि कैसे वास्तविक समय में मुद्रा विश्लेषण योग के अभ्यास में सटीकता, सुरक्षा और सुलभता को बढ़ा सकता है। यह पवेलियन आयुष के विभिन्न विषयों में नैदानिक निर्णय लेने, मानकीकरण, अनुसंधान विश्लेषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच में सहायता करने के लिए विकसित किए जा रहे एआई उपकरणों को भी प्रदर्शित करता है।

एआई और उभरती प्रौद्योगिकियां भारत के भविष्य के विकास को गति देंगीः श्री पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन का शुभारंभ किया

निर्यात प्रोत्साहन मिशन से एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होगा; भारत ने फरवरी में दोहरे अंकों की निर्यात वृद्धि दर्ज कीः श्री गोयल

निर्यात प्रोत्साहन ने एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी के साथ निर्यात फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स क्रेडिट और उभरते बाजारों के लिए सहायता आरंभ की

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत सात अतिरिक्त उपायों का शुभारंभ किया। ईपीएम वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। इन उपायों का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, व्यापक और समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।

श्री गोयल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समावेशी विकास, वंचित लोगों का सशक्तिकरण और भारत के त्वरित गति से हुए रूपांतरण में पीछे छूट गए लोगों को अवसर प्रदान करना सच्चे सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

श्री गोयल ने उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक साझेदारियों में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित किया। हाल ही में संपन्न हुए एआई समिट का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संबंधित मंत्रियों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की

प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और स्वदेशी व्यापक भाषा मॉडल में प्रगति से भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर खुलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

श्री गोयल ने इस बात पर बल दिया कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बढ़ते नेटवर्क ने भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को अत्यधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि नौ संपन्न एफटीए के माध्यम से, जिनमें अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण भी शामिल है, भारत अब वैश्विक जीडीपी के लगभग 70 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई हिस्से तक पहुंच सकता है। ये समझौते 38 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों में वरीयतापूर्ण पहुंच प्रदान करते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि भारत आज विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर रहा है। 2022 से भारत ने व्यापारिक कार्यकलापों को गति दी है, वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों में साझेदारी का विस्तार किया है, अनुपालन संबंधी बोझ कम किया है, कई कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है और व्यापार करने में सुगमता को बेहतर बनाया है। उन्होंने कई शहरों में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की भारत की सफल मेजबानी का भी उल्लेख किया, जिससे देश की विविधता और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक व्यापार के लाभ प्रत्येक लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप और उद्यमी तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उद्देश्य नए उत्पादों, सेवाओं और निर्यातकों को बढ़ावा देना है, साथ ही भारतीय व्यवसायों को नए बाजारों तक पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि फरवरी के पहले पखवाड़े में भारत ने वस्तु निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है, जो सुदृढ़ बाजार विश्वास और उद्योग की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुपालन में सहयोग देना और वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। दुबई में भारत मार्ट सहित विदेशी वेयरहाउसिंग जैसी पहलों का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को जीसीसी, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक कार्यनीतिक पहुंच प्रदान करना है।

पीएलआई ने 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत उद्योग भागीदारी को बढ़ावा दिया

पीएलआई 1.91 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना ने 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत उद्योग भागीदारी को बढ़ावा दिया है

पीएलआई योजना का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और स्थानीयकरण को बढ़ावा देना है

(जीएनएस)।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 1.91 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन बजट रखा गया है जो भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल है। 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 836 आवेदनों की स्वीकृति के साथ यह योजना उद्योग जगत के मजबूत विश्वास और इसके व्यापक उपयोग को दशार्ती है। शुरूआत से ही पीएलआई योजना को उद्योग जगत लगातार अपना रहा है और विनिर्माण क्षमता में निरंतर विस्तार हो रहा है।

31 दिसंबर 2025 तक योजना के अंतर्गत समग्र प्रदर्शन इस प्रकार हैः

स्वीकृत आवेदनः 14 क्षेत्रों में 836 आवेदन

निवेशः कुल निवेश 2.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक

उत्पादन/बिक्रीः कुल बिक्री 20.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक

निया‍र्तः कुल निर्यात 8.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक

रोजगारः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14.39 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए

प्रोत्साहन राशि का वितरणः 31 दिसंबर 2025 तक 28,748 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

ये परिणाम लक्षित क्षेत्रों में निवेश प्रवाह, उत्पादन विस्तार, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन में निरंतर प्रगति का संकेत देते हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में इस योजना के सकारात्मक प्रभाव का सारांश नीचे दिया गया हैः

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर

पीएलआई योजना ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है जिससे देश मोबाइल फोन और आईटी हार्डवेयर उत्पादों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 से मोबाइल फोन के आयात में लगभग 77 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि घरेलू मांग का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब स्थानीय उत्पादन से पूरा हो रहा है। विनिर्माण का विस्तार असेंबली से आगे बढ़कर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल, एनक्लोजर और अन्य महत्वपूर्ण सब-असेंबली तक हो गया है जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ मजबूत एकीकरण संभव हुआ है। आईटी हार्डवेयर के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता में भी विस्तार हुआ है और घटकों के प्रगतिशील स्थानीयकरण से आयात पर निर्भरता कम हुई है।

इस योजना के तहत 191 थोक औषधियों का पहली बार घरेलू उत्पादन संभव हो पाया है जिससे लगभग 1,785 करोड़ रुपये के आयात की भरपाई हुई है और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़कर 83.7 प्रतिशत हो गया है। बायोसिमिलर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और नए रासायनिक पदार्थों के स्वदेशी विकास से दवा निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ी है। इमेजिंग सिस्टम, इम्प्लांट और डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली अपनाने के कारण आयात पर निर्भरता कम हुई है।

इस योजना ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों में निवेश को गति प्रदान की है। वित्त वर्ष 2025-26 में 32,879 करोड़ रुपये की बिक्री से प्रौद्योगिकी आधारित ऑटोमोटिव विनिर्माण और आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में शुरूआती गति का संकेत मिलता है।

भारत-ब्राजील दूरसंचार सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठक

(जीएनएस)।

दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आज संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और ब्राजील गणराज्य के संचार मंत्री श्री फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

इन चर्चाओं से भारत और ब्राजील के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि हुई और समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास और तकनीकी संप्रभुता के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को एक मूलभूत स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया। ब्रिक्स ढांचे में प्रमुख साझेदारों के रूप में, दोनों पक्षों ने लचीले, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल इको-सिस्टम को आकार देने के महत्व पर बल दिया।

ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, केन्द्रीय मंत्री श्री

सिंधिया ने ब्राजील पक्ष को भारत सरकार द्वारा पिछले ग्यारह वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामर्थ्य को बढ़ावा देने और समावेशी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किए गए व्यापक प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर सबसे कम डेटा दरों इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की भारत की उपलब्धि के बारे में बताया और नागरिकों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए "सेवाओं का एक व्यापक पैकेज" सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

उपग्रह संचार एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में उभरा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में उपग्रह संचार एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा, और भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं शुरू

समावेशी एआई विकास सार्वजनिक प्रणालियों, खुले नवाचार और संतुलित वैश्विक शासन पर निर्भर करता हैः पैनल

एआई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम चेंजर हो सकता हैः जोहान्स जुट, उपाध्यक्ष, दक्षिण एशिया क्षेत्र, विश्व बैंक समूह

(जीएनएस)।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सत्र "एआई और आर्थिक प्रगति के लिए नई सीमाः समावेशी विकास के लिए नवाचार को जोड़ना" सत्र ने अगले दशक के लिए एक परिभाषित प्रश्न की जांच करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों, विकास चिकित्सकों और वैश्विक नीति विचारकों को एक साथ जोड़ा : क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्थिक विभाजन को बदाएगा या व्यापक-आधारित समृद्धि के लिए उत्प्रेरक बनेगा। एआई के नेतृत्व वाले विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक स्थितियों जिनमे उत्पादकता लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन, खुला नवाचार इकोसिस्टम और श्रम-बाजार की तत्परता चर्चा पर विचार किया गया

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मौके के बारे में बताते हुए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साउथ एशिया रीजन के वाइस प्रेसिडेंट, जोहान्स जुट ने एआईक की क्षमता पर जोर दिया कि यह सिर्फ. फ्रंटियर ब्रेकथ्रू के बजाय प्रैक्टिकल, डिप्लॉयेबल सॉल्यूशंस के जरिए डेवलपमेंट को तेज कर सकता है। उन्होंने कहा, "उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एआई गेम चेंजर हो सकता है। यह लंबे समय से चली आ रही विकास चुनौतियों को पार करने और विकास और उत्पादकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। " उन्होंने कहा कि "'छोटे एआई' पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए - व्यावहारिक, किफायती, स्थानीय रूप से प्रासंगिक एआई जो विशिष्ट समस्याओं का समाधान करता है और यहां तक कि जहां कनेक्टिविटी, डेटा, कौशल और बुनियादी ढांचा सीमित है, वहां भी काम करता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ग्रोथ और इकोनॉमी के को-डायरेक्टर, उफुक अक्सिगिट ने इनोवेशन इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की ओर ध्यान दिलाया। जहाँ एप्लीकेशन लेयर स्टार्टअप्स और नए लोगों के लिए रुकावटें कम करती है, वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि कंप्यूट-, डेटा- और टैलेंट-इंटेंसिव फाउंडेशनल लेयर पावर को कंसंट्रेट करने और लंबे समय तक चलने वाले डायनैमिज्म को धीमा करने का रिस्क उठाती है। उन्होंने कहा, 'एप्लिकेशन लेयर पर, एंट्री की रुकावटें कम हैं और यह क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए फ्रेंडली है। लेकिन फाउंडेशनल लेयर पर, एंट्री की रुकावटें बहुत ज्यादा हैं और इससे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम पैदा होती है।

कसौली सीआरआई में टेटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का होगा शुभारंभ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में टेटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली, हिमाचल प्रदेश में टिटनेस एवं वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे।

व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण दशार्ते हैं कि बच्चों में डीपीटी समूह के टीकों का व्यापक टीकाकरण करने से कई देशों में डिप्थीरिया एवं टेटनस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि, समय के साथ एंटीबॉडी का स्तर कम हो सकता है, विशेष कर डिप्थीरिया मामलों में, इसलिए बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। इसके मद्देनजर, 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने देशों को टेटनस टॉक्सॉइड (टीटी) वैक्सीन से टीडी वैक्सीन में रूपांतरित होने की सिफारिश की। इस सिफारिश की डब्ल्यूएचओ के टेटनस वैक्सीन स्थिति पत्र (2017) में और 2002 एवं 2016 में रणनीतिक सलाहकार विशेषज्ञ समूह (एसएजीई) की मंत्रणा में पुनः पुष्टि हुई।

राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी गर्भवती महिलाओं सहित सभी उम्र के लोगों के लिए भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में टीटी वैक्सीन को टीडी वैक्सीन से रूपांतरित करने की सिफारिश की है। यह बदलाव टेटनस के अलावा डिप्थीरिया से सुरक्षा बढ़ाने एवं मजबूत करने की कोशिश करता है, जबकि मातृ एवं नवजात शिशु टेटनस उन्मूलन एवं नियमित टीकाकरण गतिविधियों में प्राप्त लाभों को निरंतर बनाए रखता है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, सीआरआई ने टीडी वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है। संस्थान ने अपना विकासात्मक अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया, परीक्षण लाइसेंस प्राप्त किया, पूर्व-नैदानिक अध्ययन और चरण क् क्क और क्क्क नैदानिक परीक्षणों के लिए छूट प्राप्त की, विपणन अनुमोदन तथा निर्माण एवं बिक्री लाइसेंस प्राप्त किया, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और

केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली, हिमाचल प्रदेश से मंजूरी प्राप्त की। यह टीका अब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत शुभारंभ एवं आपूर्ति के लिए तैयार है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा द्वारा टीडी वैक्सीन का शुभारंभ करने के बाद, सीआरआई अप्रैल 2026 तक यूआईपी को 55 लाख खुराक की आपूर्ति करेगा। भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए आगामी वर्षों में आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है।

टेटनस एक गंभीर बीमारी है जिसमें मांसपेशियों में दर्दनाक अकड़न एवं ऐंठन होती है और इसके कारण मुंह खोलने में असमर्थता, निगलने एवं सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। डिप्थीरिया एक संभावित जानलेवा संक्रमण है जिससे सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति रुकना, लकवा और मौत हो सकती है।

टीडी टीका (टेनेटस और वयस्क डिफ्थीरिया टीका झ्र अवशोषित, घटित डी-एंटीजन सामग्री) दोनों टेटनस एवं डिफ्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे शुद्ध डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड और शुद्ध टेटनस टॉक्सॉइड को मिलाकर बनाया जाता है। एंटीजन एल्युमीनियम फॉस्फेट पर अवशोषित होते हैं, जो एक सहायक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और थियोमर्सल को परिरक्षक के रूप में मिलाया जाता है। टीडी वैक्सीन की शुरूआत करने का उद्देश्य किशोरों एवं वयस्कों में सुरक्षा को मजबूत करना और टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों से जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाना है।

जिलाधिकारी ने अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

कौशांबी, जिलाधिकारी ने फरियादियां के बैठने व पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने आज तहसील सिराथू का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ को तहसील में फरियादियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, समुचित पेयजल व्यवस्था एवं शौचालयां की साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थित तरीके से अभिलेखां का रख-रखाव सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्हांने राजस्व मामलों के निस्तारण में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय एवं नायब तहसीलदार न्यायालय के निरीक्षण के दौरान राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान कहा कि व्यवस्थित तरीके से अभिलेखों का रख-रखाव किया जाय एवं सी.सी.टी.वी. की क्रियाशीलता सुनिश्चित बनाए रखी जाय।

जिलाधिकारी ने लेखपाल/अमीन आदि के सर्विस बुक के अवलोकन के दौरान कहा कि सर्विस बुक अपडेट रखी जाय। उन्होंने अमीन से 10 लाख से अधिक बकायेदारां व उनसे राजस्व वसूली की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए तहसीलदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आई.जी.आर.एस. रजिस्टर/जनशिकायत रजिस्टर व तहसील रजिस्टर के अवलोकन के दौरान कहा कि शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर अंकित किया जाय तथा शिकायतां का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध किया जाय।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ओम प्रकाश सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

जिलाधिकारी ने की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों से कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाय तथा नॉट रिपोर्टेड प्रसव पर विशेष ध्यान देते हुए ट्रैक किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थियों एवं आशाओं के भुगतान में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने प्रभारी चिकित्साधिकारियों से एच.आर.पी.

महिलाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि एच.आर.पी. महिलाओं की प्रतिदिन मॉनीटरिंग किया जाय।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि ब्लड डोनेशन कैम्प लगाया जाय। उन्होंने डैशबोर्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-सिराथू व कौशाम्बी एवं अर्बन की रैंकिंग अपेक्षित न पाए जाने पर सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी को रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्हांने आर.बी.एस.के. टीम से कहा कि गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जाय कि वे आयरन/कैल्शियम की टेबलेट अवश्य खाएं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कार्ययोजना बनाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य में तेजी से प्रगति सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार एवं सी.एम.एस. डॉ. सुनील शुक्ला सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

मेट्रो सिटी की भागदौड़ में पनपती एक मासूम और फ्रेश प्रेम कहानी, पढ़ें रिव्यू

(जीएनएस)।

इस हफ्ते सिनेमाघरों में फिल्म दो दीवाने सहर में रिलीज हुई है। यह फिल्म तेज रफ्तार शहरी जीवन के बीच रिश्तों और सच्चे प्यार की तलाश को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है। मुंबई जैसे व्यस्त महानगर के बीच यह कहानी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और कमियों से बनते प्यार को सामने लाती है। फिल्म यह एहसास कराती है कि आज के दौर में प्यार परफेक्ट नहीं होता, वह उलझा हुआ, अधूरा लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत हो सकता है।

फिल्म मुंबई महानगर के दो युवाओं रोशनी श्रीवास्तव और शशांक शर्मा की कहानी है। यह एक मिलेनियल लव स्टोरी है जिसमें दोनों किरदार अपनी-अपनी असुरक्षाओं के साथ जीवन और रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शशांक एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है लेकिन उसे "श" और "स" बोलने में परेशानी होती है, जो उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। वहीं रोशनी एक मीडिया एजेंसी में काम करती है लेकिन अपने लुक्स को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करती है और खुद को छिपाकर रखने की कोशिश करती है।

दोनों के परिवार चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन दोनों इस फैसले को टालते रहते हैं क्योंकि वे खुद को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग बाहरी छवि और प्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं,

दोनों खुद को फिट करने की कोशिश में खोने लगते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वे समझते हैं कि असली कनेक्शन तभी बनता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। यह कहानी दो इम्परफेक्ट लोगों की है जो धीरे-धीरे एक-दूसरे और खुद को स्वीकार करना सीखते हैं।

परफॉर्मेंस, सिद्धांत चतुर्वेदी ने शशांक के किरदार में बेहद नियंत्रित और गहराई वाला अभिनय किया है। उन्होंने किरदार की कमजोरी को ओवरड्रामेटिक नहीं बनाया बल्कि बॉडी लैंग्वेज, हिचकिचाहट और भावनात्मक ठहराव के जरिए उसे रियल बनाया है। कई दृश्यों में उनका अंदर का डर और आत्म-संदेह बिना ज्यादा संवाद के महसूस होता है। मृणाल ठाकुर ने रोशनी के किरदार में बेहद प्रभावशाली अभिनय किया है। उन्होंने एक मॉडर्न वर्किंग वुमन की असुरक्षा, आत्म-संघर्ष और भावनात्मक मजबूती को बहुत संतुलित तरीके से दिखाया है। उनकी आंखों और साइलेंट रिएक्शन में गहरी भावनात्मक परतें नजर आती हैं। दोनों की केमिस्ट्री बेहद नैचुरल और रियल लगती है। जैसे दो लोग धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझ रहे हों। संदीपा धर का स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद असरदार है। वहीं इला अरुण अपनी उपस्थिति से कहानी में गर्माहट जोड़ती हैं।

डायरेक्शन

निर्देशक ने महानगर की पृष्ठभूमि पर आम लोगों की कहानी को बेहद स्वाभाविक तरीके से पेश किया है। दर्शक बहुत जल्दी कहानी और किरदारों से जुड़ जाते हैं। फिल्म कभी रोशनी की कहानी लगती है, कभी शशांक की – और अंत में दोनों के प्यार की कहानी बन जाती है। फिल्म क्लासिक रोमांस की सॉफ्ट फीलिंग और आज के रिलेशनशिप की रियलिटी के बीच अच्छा संतुलन बनाती है। डायलॉग्स नैचुरल, कोटेबल और यंग ऑडियंस को अपील करने वाले हैं।

फाइनल वर्डिक्ट

यह फिल्म दिखाती है कि तेज रफ्तार और भावनात्मक रूप से व्यस्त जिंदगी के बीच भी सच्चा प्यार पनप सकता है। यह कहानी बताती है कि प्यार परफेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी खूबसूरत होता है। रोशनी और शशांक के सफर के साथ फिल्म मुंबई की अफरा-तफरी से लेकर उसके पुराने चार्म और फिर पहाड़ों की शांति तक एक खूबसूरत विजुअल और इमोशनल जर्नी बन जाती है। यह फिल्म ऐसे प्यार की कहानी है जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं।

पुडुचेरी चुनाव: तमिलनाडु में सहयोगी एआईडीएमके से बीजेपी ने बनाई दूरी, एनआर कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार

(जीएनएस)।

अप्रैल-मई के महीने में संघ-शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु से सटे पुड्डेचेरी के सियासी समीकरणों काफी दिलचस्प रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल एनडीए की सरकार है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) और बीजेपी यहां मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं होगा।

विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह अक्अउ्टङ के साथ कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने यह भी दोहराया कि मौजूदा गठबंधन एन. रंगास्वामी के नेतृत्व वाली एनआर कांग्रेस के साथ पहले की तरह जारी रहेगा।

मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर एक नजर

– पुड्डुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा व्यवस्था मौजूद है। यहां कुल 30 निर्वाचित सीटें हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार 3 सदस्यों को नामित किया जाता है। यानी सदन

की प्रभावी संख्या 33 मानी जाती है।

– बहुमत का आंकड़ा सामान्यतः 30 निर्वाचित सीटों के आधार पर 16 सीटें है। हालांकि, नामित सदस्यों की मौजूदगी सत्ता संतुलन में अहम भूमिका निभा सकती है, जैसा कि पिछली सरकारों के दौरान देखा गया है।

मौजूदा सरकार का गणित

इस समय सत्ता में एनआर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। 2021 के चुनाव में सीएम रंगास्वामी की पार्टी ने 10 सीटें जीती थीं, जबकि इखढ को 6 सीटें मिली थीं। साथ ही, 3 नामित सदस्यों का समर्थन भी NDA खेमे के साथ रहा। इस तरह गठबंधन ने आराम से बहुमत का आंकड़ा पार किया। मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व में यह गठबंधन अब तक स्थिर माना जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी का एआईएडीएमके से दूरी स्पष्ट संकेत है कि पार्टी पुड्डुचेरी में स्वतंत्र पहचान और मौजूदा समीकरण के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना चाहती है।

AIADMK का फैक्टर कितना अहम?

AIADMK तमिलनाडु की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और पुड्डुचेरी की राजनीति पर भी उसका प्रभाव रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में उसका जनाधार सीमित हुआ है। बीजेपी के ताजा बयान से साफ है कि वह तमिलनाडु की राजनीति से अलग रणनीति अपनाते हुए पुड्डुचेरी में स्थानीय गठबंधन पर भरोसा कर रही है। पुड्डुचेरी में ठऊ्अ गठबंधन की परीक्षा होगी। विपक्षी इंडिया अलायंस (कांग्रेस और DMK) भी सक्रिय हैं। ऐसे में सीटों का छोटा आकार और गठबंधन की राजनीति चुनाव को बेहद रोचक बना सकती है।

डालीबाग में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का डंडा, प्लॉट संख्या 12 सील

लखनऊ। राजधानी के पॉश इलाके डालीबाग में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-6 की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बटलर रोड स्थित एक निर्माणाधीन परिसर को पूरी तरह सील कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई विहित प्राधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किए गए सीलिंग आदेश दिनांक 26.07.2025 के अनुपालन में की गई है। प्रशासन द्वारा चिन्हित यह अवैध निर्माण श्री अंकित शर्मा व अन्य द्वारा

कराया जा रहा था।

स्थान प्लॉट संख्या 12, बटलर रोड तिलक मार्ग, डालीबाग। हजरतगंज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28(क) के तहत।

सीलिंग की इस प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन जोन-6 के अवर अभियंता (JE) और सहायक अभियंता (AE) मौजूद रहे। किसी भी संभावित विरोध को देखते हुए प्राधिकरण पुलिस बल और स्टाफ की भारी तैनाती की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना नक्शा पास कराए या नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

विहित प्राधिकारी के आदेशों का पालन करते हुए आज बटलर रोड पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। नियम विरुद्ध किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

ऐरा विश्वविद्यालय के एआई स्टॉल पर उमड़ा उत्साह

कई सहयोग समझौतों के संकेत

यूपी। क्ल्र्फ अक केसूं३ र४े३ 2026 में भारत मंडपम स्थित आयोजन स्थल पर ऐरा विश्वविद्यालय के स्टॉल का तीसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल रहा।

स्टॉल पर उपस्थित श्री हरि शंकर जी (हेड आपरेशन) ने एआई आधारित हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर के प्रभावशाली परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ऐआई सिस्टम अस्पतालों में भर्ती मरीजों के दर्द और पीड़ा को कम करने, उपचार को अधिक सटीक एवं त्रुटिरहित बनाने, इलाज की लागत घटाने तथा मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

रियल-टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और अक-सक्षम ठअइछ प्रोटोकॉल के अंतर्गत मशीन लर्निंग आधारित क्लीनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम से सेप्सिस और अस्पताल में होने वाले

संक्रमण को कम करने की दिशा में यह एक अभिनव पहल है।

इसके अतिरिक्त, श्फ और एनीमेशन आधारित स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से दक्ष एवं प्रशिक्षित हेल्थकेयर वर्कर तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

स्टॉल पर अक्षरधाम के महंत जी ने भी भ्रमण किया और अपने अस्पताल के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। वहीं चार क्श्र्ऋ सेंटर के संचालक श्री गुप्ता ने सभी उत्पादों की सराहना करते हुए अपने केंद्रों के लिए समाधान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

'श्३' द४ी२३' क्विज गेम में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरे दिन स्टॉल पर उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। अनेक कंपनियों और विश्वविद्यालयों ने सहयोग के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए।

आईटी हेड श्री इसरार तथा टू फोर्मा गेम्स के हेड श्री शमीम और उनकी टीम ने उत्पादों का प्रभावी प्रदर्शन किया। क्राईटेरियन टेक के सीईओ एवं फाउंडर श्री जाव अली खान तथा डॉक्टर एम एम फरीदी डीन ऐरा विश्वविद्यालय ने आगंतुकों से मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण समझौते और सहयोग की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं।

समिट में ऐरा विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य सेवाएं भविष्य के 'स्मार्ट हॉस्पिटल' मॉडल की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।

जल शक्ति केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई ने छत्तीसगढ़ के जिला कलेक्टरों के साथ जेएसजेबी 2.0 की समीक्षा की

छत्तीसगढ़ ने जेएसजेबी 2.0 के तहत 88,000 से अधिक परियोजनाएं पूरी कीं, भूजल पुनर्भरण प्रयासों को सुदृढ़ किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों के साथ जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कंथा राव, अपर सचिव और राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती अर्चना वर्मा, छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव श्री राजेश टोप्पो और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में दुर्ग, बिलासपुर और सूरजपुर जिलों के जिला कलेक्टरों ने जेएसजेबी 2.0 के तहत जिला स्तरीय प्रगति, नवोन्मेषी पद्धतियों और समुदाय-आधारित जल संरक्षण पहलों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतियां दीं। इन जिलों ने व् यापक स् तर पर संग्रहण, योजनाओं के समन्वय और निम् न लागत वाली, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के लक्षित कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ ने जेएसजेबी 1.0 के

दौरान अल्पावधि में चार लाख से अधिक जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। राज्य के कई जिलों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और राज्य सामुदायिक जल संरक्षण में अग्रणी बनकर उभरा। जेएसजेबी 2.0 के तहत, राज्य ने 88,000 से अधिक पूर्ण परियोजनाओं और 42,000 से अधिक निमार्णाधीन परियोजनाओं की रिपोर्ट की है, जो जिलों में निरंतर प्रगति को दर्शाती है।

बैठक में छत्तीसगढ़ से उभरे सफल मॉडलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिनमें रायपुर नगर निगम के सहयोग से विकसित क्रेडाई-रायपुर का कम लागत वाला भूजल पुनर्भरण मॉडल और कोरिया जिले का "5 प्रतिशत मॉडल" शामिल है। इसके तहत किसानों ने अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा वर्षा जल पुनर्भरण के लिए समर्पित किया था। इन मॉडलों ने प्रदर्शित किया कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, निम् न लागत वाले उपाय, जब मजबूत सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित हों, तो भूजल पुनर्भरण के सार्थक परिणाम दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई ने जेएसजेबी 2.0 के तहत सभी जिलों में जल संरक्षण प्रयासों में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर मिसाल कायम करने और जिला स्तरीय प्रदर्शन को अन्य राज्यों के लिए एक मानदंड बनाने का प्रयास करेगा।

श्री सी.आर. पाटिल ने जिला संग्राहकों को संबोधित करते हुए मानसून के आगमन से पहले पर्याप्त वर्षाजल पुनर्भरण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन् द्र मोदी के नेतृत्व में जल संचय जन भागीदारी एक जन आंदोलन में रूपांतरित हो गई है, जिससे जल संरक्षण एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया है।

श्री पाटिल ने रेखांकित किया कि एमजीएनआरईजीए के तहत जल संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और जिलों से आग्रह किया कि वे 31 मार्च 2026 से पहले उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने गंभीर और अर्ध-गंभीर जिलों में केंद्रित कार्रवाई, नियमित निगरानी, जेएसजेबी पोर्टल पर समय पर डेटा अपलोड करने और समुदाय के साथ मजबूत समन्वय तथा सीएसआर भागीदारी की अपील की।

श्री सी.आर. पाटिल ने राज्य की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ जेएसजेबी 2.0 के तहत अपने प्रयासों में और तेजी लाएगा और समुदाय-नेतृत्व वाले भूजल पुनर्भरण और सतत जल प्रबंधन में नए मानदंड स्थापित करना जारी रखेगा।

राज्यसभा की चुनावी जंग में नितिन नबीन, रीना पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह?

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने राज्य का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। 16 मार्च को होने वाली वोटिंग से पहले एनडीए और महागठबंधन के खेमे में दांव-पेंच का दौर जारी है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि साख का भी है। बीजेपी जहां अपने वफादार नितिन नबीन और भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसे चेहरों पर विचार कर रही है,

वहीं चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के लिए 'सम्मान' की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा के गणित के हिसाब से एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत रहा है, लेकिन असली रोमांच 'पांचवीं सीट' को लेकर है। इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य और नीतीश कुमार की नई रणनीति भी दांव पर लगी है। संगठन में कद या राज्यसभा का पद?

बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नबीन का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। वर्तमान में वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसी बड़ी

जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर दिल्ली की राजनीति में और ज्यादा सक्रिय कर सकती है। हालांकि, पार्टी के भीतर एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि संगठन की मजबूती के लिए उनका पद पर बने रहना जरूरी है।

चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए एनडीए के भीतर पूरी राजनीतिक ताकत लगा रहे हैं। चिराग का दावा बेहद मजबूत है; लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीतकर अपनी धमक दिखाई है। चिराग का तर्क है कि इस शानदार प्रदर्शन के बदले उन्हें राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को उच्च सदन में बरकरार रखना चिराग के लिए एक बड़ा 'इमोशनल कार्ड' भी है। अगर बीजेपी इस मांग पर मुहर लगाती है, तो चिराग अपनी मां रीना पासवान को सदन भेजकर न केवल परिवार की विरासत सुरक्षित करेंगे, बल्कि अपने वोट बैंक को भी एक बड़ा संदेश देंगे।

भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है।